21-10-2021

कम चीनी बनाएं तो ज्यादा मुनाफा कमाएंगी चीनी मिलें : प्रो. नरेंद्र मोहन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : नई तकनीक और नए बाजार पर उद्योग जगत की सतत नजर रहती है, लेकिन चीनी मिल उद्योग की चाल इस दिशा में अभी बहुत धीमी है। कई देशों को चीनी संबंधी तकनीक का 'गुरुमंत्र' दे रहे कानपुर स्थित राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एनएसआइ) के निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन मानते हैं कि चीनी उत्पादन कम कर यदि चीनी मिलें शीरे से एथनाल, बगास के बर्तन सहित अन्य उत्पादन शुरू करें तो न सिर्फ उनका मुनाफा बढ़ेगा, बल्कि किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान भी नहीं अटकेगा।

उत्तर प्रदेश शुगर मिल एसोसिएशन की लखनऊ में आयोजित वार्षिक आम सभा (एजीएम) में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए प्रो. नरेंद्र मोहन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चीनी के भाव कई चीजों पर निर्भर करते हैं। वह ऊपर-नीचे होते रहते हैं, जबकि गन्ने का मूल्य सरकार के नियंत्रण में रहता है। ऐसे में चीनी उत्पादन पर निर्भरता स्थायी समाधान नहीं दे सकती। यह भी एक वजह है कि किसानों का गन्ना मूल्य लंबित हो जाता है। उन्होंने कहा कि चीनी मिलों को बिजनेस माडल अपनाना चाहिए। अभी इस दिशा में सिर्फ दस फीसद मिलें ही आगे बढ़ी हैं। अभी सभी चीनी मिलें जो सामान्य चीनी बना रही हैं, उसमें मात्र 40 फीसद की खपत हो पाती है। मांग और आपूर्ति का संतुलन सभी के लिए लाभकारी है। बेहतर हो कि सिर्फ चीनी पर निर्भरता छोड़कर बहुउत्पाद बनाए जाएं। ब्रेवरेज, फार्मा के उपयोग और निर्यात के लिए विशेष चीनी बनाई जा सकती है। इसके अलावा बगास (गन्ने की खोई) का बहुत उपयोग है। इससे इको-फ्रेंडली उत्पाद बन रहे हैं। बगास की क्राकरी की मांग तेजी से बढ़ी है। नई तकनीक को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं भी हैं।

उप शुगर मिल एसोसिएशन की वार्षिक आमसभा को बुधवार को संबोधित करते राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन। मंचासीन एसोसिएशन के अध्यक्ष सीबी पटोदिया, महासचिव दीपक गुप्तारा और शुगर फेडरेशन के प्रबंध निदेशक आरके पांडेय● जागरण

पर्याप्त हैं चीनी के मौजूदा दाम करते रहेंगे पूरा भुगतान : पटोदिया

उत्तर प्रदेश शुगर मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सीबी पटोदिया का कहना था कि चीनी की इस समय विश्व में किल्लत है। ऐसे में दाम बढ़ने चाहिए। क्या दाम बढ़ने पर गन्ना किसानों के भुगतान की समस्या नहीं रह जाएगी? इस सवाल पर उनका कहना था कि वह चाहते हैं कि किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान हमेशा समय पर हो। लगभग सभी सदस्य मिलों ने भुगतान कर भी दिया है। जिन पर बकाया है, वह एसोसिएशन के सदस्य नहीं हैं।

जल्द मिलेगा पैक गन्ने का रस : एनएसआइ निदेशक ने बताया कि गन्ने का रस अभी खुले में मिलता है। कोरोना की महामारी के बाद से लोग स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सतर्क हैं। वह इस तरह गन्ने का रस नहीं पीना चाहते। उसके प्राकृतिक स्वाद को बरकरार रखते हुए पैक्ड गन्ने का रस अन्य पेय पदार्थों की तरह बेचा जा सकता है। इस तकनीक पर उनका संस्थान शोध कर रहा है। बैठक में एसोसिएशन के महासचिव दीपक गुप्तारा, शुगर फेडरेशन के प्रबंध निदेशक आरके पांडेय आदि भी शामिल हुए।

किसानों व मिलों के बीच संतुलन के लिए चीनी मिलों को सह उत्पाद पर देना होगा जोर

● बगास से बनी बिजली के दाम में बढ़ोत्तरी की उठी मांग

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

यूपी में गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर चीनी मिलों की टकराहट को कम करने के लिए अब मिलों को चीनी के साथ-साथ सहवर्ती उत्पादों पर जोर देना होगा ताकि चीनी के भुगतान का लेकर संकट खड़ा न हो। साथ ही गन्ने की खोई से बनने वाले बिजली के दाम पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि यूपी में 2.80 रुपए प्रति यूनिट सरकार मिलों से बिजली खरीद रही है जबकि बिहार जैसे पड़ोसी राज्य बगास से बनी बिजली का दाम 6 रूपए से भी अधिक दे रहा है।

यह मुद्दे बुधवार को यूपी शुगर मिल कोजन एसोसिएशन की एजीएम में उठे। इस बैठक में उप्र राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उप्र राज्य विद्युत परिषण निगम लिमिटेड, उप्र स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, यूपी शुगर फेडरेशन के एमडी रमाकांत, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के निदेशक नरेंद मोहन समेत कोजन से बिजली का निर्माण करने वाली निजी और सरकार चीनी मिलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में कोजन से बनी बिजली की दर का मुद्दा प्रमुख रहा जिस पर सभी ने चिंता जताई। सरकार चीनी मिलों से 2.80 रूपए प्रति यूनिट के अनुसार बिजली क्रय कर रही है जबकि पहले यूपी में बगास से बनी बिजली के दाम 5.80 रूपए प्रति यूनिट थे जो बाद में कम कर दिए गए हैं। इसके अलावा मिलों ने बिजली उत्पादन के बाद उसके परिषण को लेकर आ रही दिक्कतों को भी सामने रखा जिसमें पावर कारपोरेशन और उत्पादन निगम द्वारा कोई सिंगल विंडों सिस्टम न होने से मिलों को आ रही व्यावहारिक भी साझा की गई। इस पर यूपीएसएलडीसी के अधिकारियों ने कहा कि पावर कारपोरेशन द्वारा एक नोडल अधिकारी और एक टोल फ्री नंबर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है जिस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। शुगर मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सीबी पटौदिया ने कहा कि बगास से बनने वाली बिजली के दाम अन्य राज्यों की तुलना में यूपी में काफी कम हैं। उप्र राज्य विद्युत नियामक आयोग में प्रस्ताव दिया गया था कि कम से कम बगास के जो दाम हैं उसी के अनुसार कोजन इनर्जी के दाम निर्धारित किए जाएं ताकि किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान में कठिनाई न हो सके। प्रदेश सरकार से इस बारे में वार्ता चल रही है, हो सकता है कि कोई सकारात्मक हल निकल सके। बैठक को एमडी यूपी शुगर फेडरेशन रामाकांत, मुख्य अभियंता उप्र राज्य विद्युत परिषण निगम अमलेंदु, यूपीएसएलडीसी के एचडी दुबे, शुगर एसोसिएशन के दीपक गुप्तारा, पंकज रस्तोगी सीईओ डालमिया समूह, समेत अन्य मिलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

यूपी में एक साल के भीतर ट्रेट्रा पैक में मिलेगा गन्ने का रस

लखनऊ। बैठक में आए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के निदेशक नरेंद्र मोहन ने कहा कि बाजार मिलने वाले तमाम फ्रूट जूस उतने लाभप्रद नहीं होते जितने वह दर्शाते हैं। कोविड महामारी के बाद प्राकृतिक चिकित्सा की मांग बढ़ी है और हम इस बात पर शोध कर रहे है कि गन्ने का रस भी लोगों को बाजार में पैक किया हुआ मिले जो ताजा और स्वास्थ्य वर्धक हो, क्योंकि बाजारों में खुले में बिकने वाला गन्ने का पीना हर कोई चाहता है लेकिन साफ-सफाई के आभाव में लोग नहीं पीते हैं। उन्होंने जिस पर बाजार में कोल्ड ड्रिंक की मार्केट है उसी प्रकार अगर मिलें गन्ने का रस भी बेचेंगी तो बाजार में अच्छा बिजनेस मिलेगा। इसके लिए संस्थान ने कई स्तर के शोध पूरे कर लिए हैं और उम्मीद है कि अगले एक साल के भीतर हम इसे बाजार में उतार सकेंगे। उन्होंने कहा कि यूपी में गन्ने मूल्य भुगतान को लेकर चीनी मिलों के पास संकट रहता है इसलिए अगर मिले इस प्रकार के सहवर्ती उत्पाद बनाएगी तो उन्हें भुगतान में कठिनाई नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि मिलों को एग्रो बिजनेस काम्पलेक्स के रूप में काम करना होगा। जिसमें एक्सपोर्ट, बैजरेज, मेडिसिन, कन्फेक्शनरी सेक्टर में जरूरत के अनुसार चीनी का उत्पादन किया जा सके। मिलो को इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का भी निर्माण करना होगा। इसमें बगास से बनने वाली डिस्पोजल क्राकरी, बगास से बनने वाली प्लाई, केमिकल, खाद्य पदार्थों में उपयोग किए जाने वाला वनीला जैसे उत्पादों का निर्माण किया जाना आवश्यक है।

कार्यालय — नगर पालिका परिषद खलीलाबाद, जनपद—संतकबीरनगर

कम चीनी बनाकर ज्यादा मुनाफा कमा सकती हैं चीनी मिलें : प्रो. नरेंद्र मोहन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : नई तकनीक और नए बाजार पर उद्योग जगत की सतत नजर रहती है, लेकिन चीनी मिल उद्योग की चाल इस दिशा में अभी बहुत धीमी है। कई देशों को चीनी संबंधी तकनीक का 'गुरुमंत्र' दे रहे कानपुर स्थित राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एनएसआइ) के निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन मानते हैं कि चीनी उत्पादन कम कर यदि चीनी मिलें शीरे से एथनाल, बगास के बर्तन सहित अन्य उत्पादन शुरू करें तो न सिर्फ उनका मुनाफा बढ़ेगा, बल्कि किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान भी नहीं अटकेगा।

उत्तर प्रदेश शुगर मिल एसोसिएशन की लखनऊ में आयोजित वार्षिक आम सभा (एजीएम) में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए प्रो. नरेंद्र मोहन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चीनी के भाव कई चीजों पर निर्भर करते हैं। वह ऊपर-नीचे होते रहते हैं, जबकि गन्ने का मूल्य सरकार के नियंत्रण में रहता है। ऐसे में चीनी उत्पादन पर निर्भरता स्थायी समाधान नहीं दे सकती। यह भी एक वजह ह कि किसानों का गन्ना मूल्य लंबित हो जाता है।

उन्होंने कहा कि चीनी मिलों को बिजनेस माडल अपनाना चाहिए। अभी इस दिशा में सिर्फ दस फीसद मिलें ही आगे बढ़ी हैं। अभी सभी

- अब तक दस फीसद चीनी मिलें ही अपना सकी हैं बिजनेस माडल
- विशेष चीनी, एथनाल, बगास की क्राकरी जैसे उत्पाद बढ़ाएंगे आय

चीनी मिलें जो सामान्य चीनी बना रही हैं, उसमें मात्र 40 फीसद की खपत हो पाती है। मांग और आपूर्ति का संतुलन सभी के लिए लाभकारी है। बेहतर हो कि सिर्फ चीनी पर निर्भरता छोड़कर बहुउत्पाद बनाए जाएं। बेवरेज, फार्मा के उपयोग और निर्यात के लिए विशेष चीनी बनाई जा सकती है।

इसके अलावा बगास (गन्ने की खोई) का बहुत उपयोग है। इससे ईको-फ्रेंडली उत्पाद बन रहे हैं। बगास की क्राकरी की मांग तेजी से बढ़ी है। नई तकनीक को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं भी है।

जल्द मिलेगा पैक गन्ने का रस

एनएसआइ निदेशक ने बताया कि गन्ने का रस अभी खुले में मिलता है। कोरो की महामारी के बाद से लोग स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सतर्क है। वह इस तरह गन्ने का रस नहीं पीना चाहते। उसके प्राकृतिक स्वाद को बरकरार रखते हु पैक्ड गन्ने का रस अन्य पेय पदार्थों की तरह बेचा जा सकता है। इस तकनीक पर उनका संस्थान शोध कर रहा है।

पर्याप्त है चीनी के मौजूदा दा करते रहेंगे पूरा भुगतान : उ प्रदेश शुगर मिल एसोसिएशन अध्यक्ष सीबी पटोदिया का कह था कि चीनी की इस समय विश्व किल्लत है। ऐसे में दाम बढ़ने चाहि क्या दाम बढ़ने पर गन्ना किसानों भुगतान की समस्या नहीं रह जाएग इस सवाल पर उनका कहना था वह चाहते हैं कि किसानों के ग मूल्य का भुगतान हमेशा समय हो। लगभग सभी सदस्य मिलों भुगतान कर भी दिया है। जिन बकाया है, वह एसोसिएशन के सद नहीं हैं।

वार्षिक सामान्य बैठक एसोसिएशन के महासचिव दीप गुप्तारा, शुगर फेडरेशन के प्रब निदेशक आरके पांडेय सहित अ पदाधिकारी भी शामिल हुए।

एनएसआइ | गुड़ और खांडसारी इकाई में बनेगा लिक्विड, फ्लेवर्ड व क्यूब

बनेगा गुड़ - खांडसारी का इनोवेशन सेंटर

जासं, कानपुर : एनएसआइ गुड़ और खांडसारी के क्षेत्र में उद्यमिता विकास कराएगा। यहां के विशेषज्ञ सामान्य गुड़ और खांडसारी से जहां लिक्विड, फ्लेवर्ड, क्यूब, फोर्टिफाइड गुड़ और गुड़ पाउडर बनाना सिखाएंगे। वहीं, इनसे चाकलेट, बिस्कुट, केक, पेस्ट्री और अन्य बेकरी व कनफेक्शनरी उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण देंगे। छात्रों के इसी फार्मूले पर अन्य प्रोडक्ट बनाने की विधा को पेटेंट कराया जाएगा। संस्थान में सेंटर फार इनोवेशन इन गुड़ एंड खांडसारी खुलने जा रहा है। यह 37 वर्षों से बंद खांडसारी एवं गुड़ उत्पादन इकाई में चालू किया जाएगा। एनएसआइ की ओर से उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को दो करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेज गया है। मंत्रालय की ओर से सैद्धांतिक सहमति मिल गई है।

संस्थान में खांडसारी और गुड़ की इकाई उदासीनता व रखरखाव के अभाव में बंद हो गई थी। पिछले दिनों खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सचिव डा. सुधांशु पांडेय ने निरीक्षण किया था। उन्होंने बंद इकाई को चालू कराकर रोजगारपरक कोर्स संचालित करने का निर्देश दिया। एनएसआइ निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन ने प्रस्ताव तैयार कराया। प्रो. नरेंद्र मोहन ने बताया कि मशीनें खराब हो चुकी हैं। उनका उच्चीकरण कराया जाएगा। कुछ मशीनें तो पुरानी तकनीक पर आधारित हैं। इकाई के चालू होने पर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

सेंटर में कनफेक्शनरी और बेकरी आइटम, लिक्विड, फ्लेवर्ड, क्यूब, फोर्टिफाइड गुड़ और गुड़ पाउडर बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

कम चीनी बनाएं तो ज्यादा मुनाफा कमाएंगी चीनी मिलें

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एनएसआइ) के निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन मानते हैं कि चीनी उत्पादन कम कर यदि चीनी मिलें शीरे से एथनाल, बगास के बर्तन सहित अन्य उत्पादन शुरू करें तो मुनाफा बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश शुगर मिल एसोसिएशन की लखनऊ में आयोजित वार्षिक आम सभा (एजीएम) में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए प्रो. नरेंद्र मोहन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चीनी के भाव कई चीजों पर निर्भर करते है। वह ऊपर-नीचे होते रहते हैं, जबकि गन्ने का मूल्य सरकार के नियंत्रण में रहता है। ऐसे में चीनी उत्पादन पर निर्भरता स्थायी समाधान नही दे सकती। यह भी एक वजह ह कि किसानों का गन्ना मूल्य लंबित हो जाता है।